(7) On the advices of the Government of India, Reserve Bank of India has set up State Level Inter-Institutional Committees (SLIICs) in all States under the Chairmanship of Secretary, Industries Department of the concerned State Governments for working out a rehabilitation package for revival of viable sick small scale units.

(8) Financial assistance in the form of long term equity type assistance upto Rs. 1,50,000/- to units with a project cost not exceeding Rs. 10 lakhs at a nominal service charge of one percent per annum is also available to potentially viable sick small scale industrial units from the National Equity Fund set up in August, 1987.

(9) The Union Ministry of Industry is also operating a Centrally sponsored Margin Money Scheme for revival of sick small scale units, under which quantum of assistance per unit is upto Rs. 50,000/-.

(10) Small Industries Development Bank of India (SIDBI) has been established to function as an Apex Bank for tiny and small industries.

A separate Refinance Scheme for Rehabilitation (RSR) is being managed by SIDBI for revival of potentially viable sick small scale industrial units.

NRI sponsored Projects

3008. SHRI RAJUBHAI PARMAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of NRI sponsored industrial projects submitted during 1991-92, since July, 1991 and 1992-93 so far particularly those for being set up in Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat; and

(b) the details of such projects already cleared and the stage of development of each one of them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) After the new liberalisation policy announced by the Govt. in July, 1991, several proposals involving foreign investments including NRI investment, have been approved in different sectors viz. automobile, chemicals, engineering, electronics, etc. in the country, including Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat, as per break-up given below:—

	(Rs. in million)
August, 1991 to December, 1991	4133.4
1992	38875.4
January to February, 1993	23800.00

The gestation period of an industrial project varies from project to project, and industry the industry.

विपणन विकास निगम की स्थापना

3009. **श्री राम नरेश यादव :** क्या प्रधान मंत्री 17 दिसम्बर, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 3700 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग ने एक विपणन विकास निगम की स्थापना का प्रस्ताव बनाकर भेजा था ;

(ख) क्या सरकार को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से पुराने प्रस्ताव के स्थान पर नया प्रस्ताव प्राप्त हो गया है जिसे इस अनुरोध के साथ वापस भेज दिया गया था कि उसे परिशोधित किया जाए ;

(ग) क्या यह भी सच है कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने बिना सरकार से स्वीकृति लिए विपणन विकास निगम पर कार्य आरम्भ कर दिया है और इस पर धनराशि खर्च की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य को आरम्भ करने के क्या कारण हैं और ऐसे मामलों में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) :(क) से (घ) जी, हां। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी तथा ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए एक विपणन विकास निगम स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। योजना आयोग के साथ परामर्श करके इस प्रस्ताव की जांच की गई थी और की गई टिप्पणियों के आधार पर के०वी०आई० सी० ने प्रस्ताव की पुनः जांच करने और इसे सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। तदनुसार, के०वी०आई०सी० ने इस विभाग को एक संशोधित प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव की जांच की गई और के०वी०आई०सी० से इस विभाग को कुछ और जानकारी देने के लिए कहा गया है। इस बीच, के०वी० आई०सी० को निदेश दिया गया है कि सरकार की स्वीकृति मिलने तक प्रस्तावित निगम के गठन के बारे में कार्रवाई न करें। के०वी०आई०सी० ने सूचित किया है कि भारत सरकार की स्वीकृति के बिना विपणन विकास निगम का कार्य अभी शुरु नहीं हुआ है।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के संबंध में ज्ञापन

3010. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली तथा खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग के बारे में कुछ पत्र, ज्ञापन आदि हाल ही में प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ; और

(ग) क्या सरकार ने आगे की कार्यवाही रोकने के लिए कोई अनुदेश दिये हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम):(क) से (ग) खादी ग्रामोद्योग भवनों सहित खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के बारे में सरकार को समय-समय पर अनेक अभ्यावेदन मिलते रहते हैं। जब भी ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तो सरकार इन मामलों की जांच करती है और उचित कार्यवाही करती है।

किन्तु सरकार को अभी हाल ही में खादी ग्रामोद्योग भवन कर्मचारी संघ की ओर से दिनांक 29-1-93 का एक पत्र मिला है जिसमें खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अधीन एक विपणन विकास निगम गठित नही करने का अनुरोध किया गया है। सरकार ने खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को आदेश दिया है कि वह सरकार की पूर्वानुमति लिए बिना इस प्रकार का निगम गठित करने के बारे में आगे कोई कार्यवाही न करे।

Net profits of PSUs

3011. SHRI SUKOMAL SEN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that net profits of the Central PSUs for 1991-92 have substantially increased over that of the preceding year;

(b) if so, the details of the companies making profits and those incurring losses; and

(c) the reasons for making profits by some companies and making losses by others?